सच्चाई और अच्छाई अगर हमारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं है।
– अज्ञात

सामाजिक विकास में हमारा मुकाम

साफ है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के जरिए अपना विकास करने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। आजादी के वक्त हमारा समाज सामंती संरचना में जकड़ा हुआ था। सामाजिक बंधनों के कारण हर किसी के समान रूप से विकसित होने की गुंजाइश नहीं के बराबर थी।

अमित शर्मा।

भारत से जुड़ी विकास की तमाम कहानियों के बावजूद सचाई यह है कि सामाजिक विकास में हमारा मुकाम दुनिया में अब भी काफी नीचे है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की 50वीं सालाना बैठक से पहले जारी 'ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स' की 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान दिया गया है। डेनमार्क इसमें टॉप पर है, इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड का नंबर है। यह इंडेक्स तैयार करने के लिए जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया है, वे हैं– स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, रोजगार, सुरक्षा और सांस्थानिक स्थिति।

भारत को जिन बातों का खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है, उनमें सामाजिक सुरक्षा और समान काम के लिए समान वेतन शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 'अगर कोई देश ऐसा माहौल तैयार करने में सफल रहता है, जहां हर किसी को अपनी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलता है, तो इसका न सिर्फ समाज को सीधा लाभ होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को हर साल अरबों डॉलर का फायदा भी होने लगेगा।'

रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां सिर्फ कुछेक अर्थव्यवस्थाओं में ही मौजूद हैं जिनमें चीन, अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी शामिल हैं। साफ है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के जरिए अपना विकास करने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। आजादी के वक्त हमारा समाज सामंती संरचना में जकड़ा हुआ था। सामाजिक बंधनों के कारण हर किसी के समान रूप से विकसित होने की गुंजाइश नहीं के बराबर थी। मगर हमारे संविधान ने हर किसी को बराबरी के अधिकार दिए और सरकारों को बिना किसी भेदभाव के सबके हित में काम करने का दायित्व सौंपा। बाद में देश में आरक्षण और इस तरह की कई अन्य नीतियां भी अपनाई गईं जिनसे वंचित तबकों को आगे आने के अवसर मिले। इसका फायदा दिख रहा है, लेकिन विकास का लाभ आज भी हर किसी तक नहीं पहुंचा है और सामाजिक–आर्थिक स्तर पर एक गहरी खाई साफ नजर आती है।

इसकी कुछ जवाबदेही हमारे देश में पिछले तीन दशकों से अपनाई गई व्यवस्था पर जाती है, जिसमें सरकारों का रोल कम होता गया है और ज्यादातर काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा चुका है। इससे विकास की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन साथ में यह नुकसान भी हुआ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के दो स्टैंडर्ड बन गए हैं। निजी क्षेत्र द्वारा दी जा रहीं क्वालिटी सुविधाएं महंगी होने के चलते बेहतर आर्थिक स्थिति वालों को ही मिल पाती हैं। इस तरह साधन संपन्न तबका विकास का ज्यादा लाभ लेने की स्थिति में पहुंच गया है, जबकि सरकारी साधनों पर आश्रित बाकी समाज दिनोंदिन पिछड़ता ही जा रहा है। इस बुनियादी बीमारी का इलाज किए बिना, सिर्फ बीच–बीच में किए जाने वाले राहत उपायों के सहारे हालात कुछ खास नहीं बदलने वाले।

प्रत्यक्ष अनुभव

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

बुद्ध की मृत्यु के 400 साल बाद लिखा गया उनका दर्शनशास्त्र तीन पिताका में विभाजित किया गया है। विनयपिताका में साधु के लिए आचरण के नियम हैं, सुत्तपिताका में बुद्ध की आध्यात्मिक प्राप्ति की व्यवहारिक विधियों के बारे में बातचीत है, और अभिधम्मपिताका में मनोविज्ञान और नैतिकता पर बुद्ध की तकनीक है।

उनकी विधियां सिद्धांतों के बारे में नहीं बल्कि आचरण के बारे में हैं। दूसरा, बुद्ध वास्तविकता, आत्मन और ब्रह्म की अनंत प्रकृति से संबंधित सारी आध्यात्मिक चर्चा को 'बेकार की बातें' कहते हैं। उनके अनुसार, इस तरह की बातों का लक्ष्य जमीनी हकीकत को भुलाकर उत्सुकता को शांत करना है।

संपादकीय

नई आजादी को नया आयाम

ई–बाजार ने परम्परागत बाजार की खामियों से भी मुक्ति दिलाई है, जिसकी वजह से इसका ट्रेड बढ़ा है। बाजारवाद की नई आजादी को नया आयाम मिला है। अगर आपकी जेब, वायलेट और बैंक में पैसा है तो घर से बजार जाने की जरूरत नहीं है। जीवन की सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। मध्यमवर्गीय परिवार इस बाजारवाद का अधिक शिकार हो रहा है। घर में बच्चों की एक डिमांड पर स्वीगी और जोमैटो की सुविधा मौजूद है। बच्चों में मिटापे एक वजह यह भी है।

ई–बाजारवाद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसा फेंको और तमाशा देखो की नीति का अनुसरण किया जा रहा है, जबकि हमारे ट्रेडिशनल बाजार में ऐसी बात नहीं है। आप शहर में हैं या गांव में तो वहां आपके पास पैसा न होने पर भी आपको राशन, दूध , फल , चाय–नाश्ता और दूसरी वस्तुएं एक निश्चित सीमा के लिए मिल जाएंगी। आप नौकरी पेशा हैं और आपकी जेब समय से पहले खाली हो गई तो परम्परागत बजार आपकी जरूरत का ख्याल रखता है।

ट्रेडिशनल बजार मानवतावादी नजरिया रखता है जबकि ई– बजार में व्यापार पहली प्रथमिकता है। भारत के साथ दुनिया में ई– बाजार की सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि खुले बाजारवाद में हमें देशी और कुटीर उद्योग को उस स्पर्धा में खड़ा करना होगा। सरकार को मझोले व्यापारियों की नाराजगी का हल निकालना चाहिए। देश में कुटीर उद्योग और उद्यमियों को बचाया जा सके। ऑनलाइन बाजार पर नियंत्रण जरूरी है। देशी बाजार को बढ़ावा देना सरकार और देश के लोगों का राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व है।

वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पीएमओ से समय नहीं मिला। क्योंकि सरकार देशी व्यापार संगठनों की नाराजगी नहीं लेना चाहती थीं, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव हैं।

बेजोस से क्यों नहीं मिले मोदी?

प्रभुनाथ शुक्ल।

भारत में ई–बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुटीर और ट्रेडिशनल बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अर्थव्यवस्था में बाजार एक अहम कड़ी है, लेकिन इसका विकेंद्रीकरण हो चला है। यूं कहे तो ग्लोबल दुनिया में पूरा बाजार मुट्ठी में हो गया है। अब भोजन से लेकर जीवन की आद्य और मॉडर्न सुविधाएं आपके बेडरूम में फैली हैं। आपके पास पैसा है तो जोमैटो और स्वीगी जैसे सुविधाएं कुछ मिनटों में आपकी डायनिंग टेबल पर होंगी। शहर तो शहर गाँव की झोपड़ी तक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडिल जैसी कम्पनियां चाहत, पसंद और सुविधा के अनुसार डिलिवरी कर रहीं हैं। ऑनलाइन बाजार ग्राहक को खुला विकल्प दे रहा है। चॉइस की आजादी है और बाजार से कम कीमत पर सामान और सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह दीगर बात है कि उसमें टिकाऊपन कितना है। भारतीय परंपरागत बाजार में छाई मंदी का यह भी एक बड़ा कारण है, लेकिन ग्लोबल होती दुनिया में ई–बाजार की पैठ तेजी से बढ़ रही है जबकि ट्रेडिशनल बजार डूब रहा है। हालात यह है कि चाइना हमारे बजार पर पूरी पकड़ बना चुका है। चीन से भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है।

सीईओ जेफ बेजोस हाल में भारत के दौरे पर थे। भारतीय व्यापारियों ने उनकी भारत यात्रा का पुरजो विरोध भी किया। वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पीएमओ से समय नहीं मिला। क्योंकि सरकार देशी व्यापार संगठनों की नाराजगी नहीं लेना चाहती थीं, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव हैं, जिसकी वजह से सरकार ने फूंक–फूंक कर कदम रखा है। पीएम से उनकी मुलाकात का मुख्य उद्देश्य था कि वह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाना चाहते थे। वह सात हजार करोड़ के निवेश के साथ 70 हजार करोड़ के भारतीय उत्पादों के निर्यात की घोषणा की थीं। बेजोस ने भारत की खूब प्रसंशा भी की लेकिन बात नहीं बन पाई, क्योंकि छोटे और मझोले कारोबारी ई–बाजार से बेहद खफा हैं। हालांकि, बेजोस की भारत प्रसंशा के पीछे उनका बाजारवाद का फंडा छुपा था। अपनी भारत यात्रा में इसे सफल नहीं कर पाए। इसका उन्हें बेहद मलाल रहेगा।

भारत क्या बेजोस की नीतियों से खफा है, अगर नहीं तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, जबकि भारत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विदेशी विनिवेश पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जब अमेजन भारतीय उत्पादों को दुनिया तक पहुंचना चाहती है तो उसे मौका क्यों नहीं दिया गया। इसकी वजह मानी जा रहीं है कि बेजोस दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की अपने अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में तीखी आलोचना की थी। कश्मीर से धारा द्र 370 हटाए जाने पर एक शृंखला का भी प्रकाशन किया था। वहीं अमेरिका में पीएम मोदी को गोल कीपर अवॉर्ड दिए जाने पर सवाल भी खड़े किए थे, जिसकी वजह से उन्हें पीएमओ ने मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। हालांकि इसकी दूसरी वजहें भी हो सकती हैं , लेकिन मीडिया में यही कयास लगाए गए हैं। फिलहाल यह सरकार का नीतिगत फौसला है उस कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं।

अष्टयोग-4927

3			6	4		1
4	33	4	40	7	31	2
	2	6	3		1	
1	29		37		35	5
	1		4	3	5	
6	30	2	24	1	30	3
5		1	4			7

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4926 का हल

1	2	3	7	5	6	4
3	29	6	37	2	31	1
4	3	7	1	6	2	5
5	29	1	33	4	37	6
6	1	2	5	7	4	3
2	33	4	31	3	30	7
7	6	5	4	1	3	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

टैक्स में कटौती

मुकुल श्रीवास्तव।

सरकार देश में खपत बढ़ाकर ही इकॉनमी में तेजी ला सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा हम आयात पर खर्च करते हैं। खपत बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट सहित कई कदम उठाने होंगे। बाजार में और धन की जरूरत है। रीयल एस्टेट को और बढ़ावा देना जरूरी है क्योंकि कृषि के बाद यह सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इसके अलावा कृषि में भी और निवेश की दरकरार है तथा किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने की जरूरत है। कई सेक्टरों में टैक्स कटौती के अलावा अन्य तरह के इंसेटिव की भी जरूरत है। समस्या यह है कि टैक्स में कटौती के भी कई बार वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं, जैसा कि कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हमने देखा। वित्त मंत्री ने इसमें 8 पर्सेंट तक की कटौती कर दी, इसके बावजूद बड़े उद्यमियों ने कोई नया निवेश नहीं किया और सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहरहाल, स्थिति जो भी हो, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर इस बजट में काफी धन देना होगा।